

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्री शंकर

विपक्षी :-श्री प्रकाशचन्द्र वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 21/25

जीसीएमएस नम्बर :-2025/75

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 23.04.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की भूमि होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 301 पर दर्ज आराजी नम्बर 1638 रकबा 0.2023 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 79 पर दर्ज आराजी नम्बर 1636 रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।</p> <p>न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं परन्तु विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा मौके के फोटोग्राफस पेश किये जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस कारण यदि मौके पर निर्माण कर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है तो इससे दोनों की पक्ष को काफी परेशानियों</p>	

का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि केवल विपक्षी संख्या 1 को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। प्रकरण में दिनांक 09.09.2025 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना आवश्यक हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा दुंढिया पटवार हल्का दुंढिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 301 पर दर्ज आराजी नम्बर 1638 रकबा 0.2023 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 79 पर दर्ज आराजी नम्बर 1636 रकबा 0.2266 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली